उमा प्रचार

वर्ष 12 अंक 45

अप्रैल से जून 2009

हम हैं हिवरे बाजार के

प्रशांत दुबे

शांत किंतु सफल शुरुआत

ललित माथुर

एक अक्षय–ई केंद्र के लिए कुछ आंसू

रीमा नरेंद्रन

पता नहीं हिवरे गांव के नाम में बाजार शब्द कैसे जुड़ गया। लेकिन आज जब देश का एक बड़ा भाग – सरकार, शहर, गांव, संस्थाएं भी बाजार जैसी होती जा रही हैं, तब यह गांव अपने काम से, जीवन से बाजार हटाता जा रहा है –वह भी उस नई पीढ़ी के प्रयास से, जो इस बाजार पर ही टिकी है। इस गांव के बारे में बता रहे हैं – प्रशांत दुबे।

आंध्र प्रदेश सरकार ने बहुत ही शांत तरीके से सूचना के अधिकार नियम का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत की है। इस काम में सरकार का पूरा सहयोग है। इस अंक में प्रस्तुत है – सामाजिक अंकेक्षण के पहले चरण की सफलता के किस्से। प्रस्तुतकर्ता हैं – ललित माथुर।

अक्षय यानी जिसका क्षय न हो। ई साक्षरता केरल राज्य की बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना थी। पंचायतों के माध्यम से कम्प्यूटर सिखाने के लिए अक्षय केंद्र खोले गये थे। राज्य और जिले की राजनीति में बहुत जल्दी ही इन अक्षय केंद्रों का तो क्षय हुआ ही। इन्हें चलाने वाले भी इससे बच नहीं पाए हैं। तिरुवनंतपुरम के पहले अक्षय–ई केंद्र के ठेकेदार सोमसुंदरम आज आर्थिक क्षय का सामना कर रहे हैं।

रीमा नरेंद्रन के लेख से आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

केवल निजी वितरण के लिए

हम हैं हिवरे बाजार के

प्रशांत दुबे

एक गांव जहां के लोग गांव का नाम अपने उपनाम के रूप में लगाते हैं। एक गांव जहां व्यापक मंदी के इस दौर का कोई असर दिखाई नहीं देता है। एक गांव जहां से अब कोई पलायन नहीं करता है। एक गांव जहां कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है। एक गांव जहां के शिक्षक स्कूल से गायब नहीं होते। एक गांव जहां की आंगनबाड़ी रोज खुलती है। एक गांव जिसके बच्चे कुपोषित नहीं हैं। एक गांव जहां राशन व्यवस्था ग्राम सभा के अनुसार संचालित होती है। एक गांव जिसकी सड़कों पर गंदगी नहीं होती। एक गांव जिसे जल संरक्षण का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एक गांव जिसका हर घर गुलाबी रंग से पुता है। एक गांव जहां गांव के एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए भी मस्जिद है।

यह उस गांव का वर्णन है जहां सत्ता दिल्ली, मुंबई में बैठी किसी सरकार द्वारा नहीं, बल्कि उसी गांव के लोगों द्वारा संचालित होती है। यह सपना–सा ही लगता है, लेकिन यह सपना साकार हो गया है महाराष्ट्र अहमदनगर जिले के गांव हिवरे बाजार में।

गांधीजी ने कहा था कि 'सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए बीस आदमी नहीं चला सकते। वह तो नीचे से हरेक गांव में लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। सत्ता के केंद्र इस समय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे नगरों में हैं। मैं उसे भारत के सात लाख गांवों में बांटना चाहूंगा।' गांधीजी का यह संदेश हमेशा एक आदर्श वाक्य की तरह लगता रहा है। इस आदर्श वाक्य को हिवरे बाजार ने अपने घरों, खेतों, गांवों में साकार कर दिया है।

बात कोई बहुत पुरानी नहीं है। सन् 1989 में हिवरे बाजार के कुछ पढ़े–लिखे नौजवानों ने यह बीड़ा उठाया कि क्यों न अपने गांव को संवारा जाये। गांव वालों से बातचीत की गई तो गांव वालों ने 'कल के छोकरे' कह कर एक सिरे से नकार दिया। युवकों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गांव वालों ने भी युवकों की चुनौती को गंभीरता से लिया और 9 अगस्त को नवयुवकों को एक वर्ष के लिए सत्ता सौंप दी। सत्ता मिली तो नवयुवकों ने सत्ता सौंपी पोपटराव पवार को। पोपटराव उस समय महाराष्ट्र की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेलते थे।

युवकों ने इस एक वर्ष को एक अवसर के रूप में देखा। गांव में सभा बुलाई। सब लोग आयें – इस बात की कोशिश की गई। सबकी राय से तय हुआ कि क्या–क्या काम तुरंत करना चाहिए। बिजली, पानी के बीच बात शिक्षा की भी आई। सामूहिक सहमति बनी शिक्षा के सवाल पर। इस समय स्कूल में शिक्षक बच्चों से शराब मंगाकर कक्षा में ही पीते थे। स्कूल में न तो खेल का मैदान था और न बैठने के लिए बैंचें थीं। ग्राम सभा में सबसे पहले युवकों ने गांव वालों से अपील की कि अपनी बंजर पड़ी जमीन को स्कूल के लिए दान दें। शुरू में तो दो परिवार तैयार हुए बाद में कई। वहां एक कमरा बनाने के लिए 60,000 रुपए की राशि तुरंत दान में आई। उचित नियोजन और गांव वालों के श्रमदान की बदौलत एक कमरे की राशि में दो कमरों का निर्माण किया गया। यह युवकों का गांव वालों को विश्वास देने वाला एक काम बन गया था। एक वर्ष खत्म हुआ, समीक्षा हुई। गांव वालों ने अब इन नवयुवकों को पांच वर्षों के लिए सत्ता सौंपने का निश्चय किया।

पोपटराव के कुशल नेतृत्त्व में युवकों ने गांव की कुछ मोटी–मोटी बातें समझना शुरू किया। गांव में औसतन प्रति व्यक्ति सालाना आय 800 रुपए थी। गांव के हर परिवार से लोग कुछ कमाने के लिए शहर पलायन करते थे। गांव में रह जाते थे केवल बूढ़े, महिलाएं और बच्चे। कुछ लोगों के पास जमीन थी, पर वे केवल एक फसल ले पाते थे। सिंचाई के लिए पानी तो था ही नहीं। यहां कुल मिलाकर 400 मि.मी. वर्षा होती थी। पोपटराव कहते हैं कि हमने सामूहिक रूप से इस विषय पर सोचना शुरू किया। पहले गांव वाले वन विभाग द्वारा लगाए पौधों को ही काट कर ले जाते थे। जब हमने तय किया कि भू–सुधार और जल संरक्षण के काम किए जाएंगे तो हमने दस लाख पेड़ लगाने का निश्चय किया और उसमें हम 99 प्रतिशत सफल हुए। अब इस जंगल में

जाने के लिए वन विभाग को भी ग्राम सभा की अनुमति लेनी होती है। पोपटराव कहते हैं कि शुरू में कई निर्णयों पर बहुत विरोध हुआ। जवाब में हमने कहा कि गांव के हित में यह निर्णय ठीक होगा, इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। जैसे खेती के लिए ट्यूबवैल उपयोग नहीं किए जाएंगे और ज्यादा पानी वाली फसलें नहीं लगाई जाएंगी। गन्ना केवल आधे एकड़ में ही लगाया जाएगा, जिसका हरे चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये सब निर्णय कठोर थे, कठिन थे, कड़वे थे। पर सबको बिठाकर आगे तक देखना सीखा, सिखाया तो ये सब बातें लागू भी हो गईं।

पोपटराव ने बताया: हम सबने मिलकर पानी का काम करना शुरू किया। कुछ सरकारी राशि और कुछ श्रमदान। तीन–चार वर्षों बाद इस काम ने अपना असर दिखाना शुरू किया। भूजल स्तर बढ़ा और मिट्टी में नमी बढ़ने लगी। लोगों ने दूसरी और तीसरी फसल की ओर रुख किया। अब यहां सब्जी भी उगाई जाती है। जिनके पास जमीन नहीं है, अब उन्हें पहले की तरह गांव से शहर नहीं भागना पड़ता। रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन बंद हुआ। ग्राम की ही ताराबाई मारुति कहती हैं, 'पहले मजदूरी करने हम लोग दूसरे गांव जाते थे। आज हमारे पास 16–17 गायें हैं और हम हर दिन ठीक मात्रा में दूध बेचते हैं। पूरे गांव से लगभग, 5000 लीटर दूध प्रतिदिन बेचा जाता है। आज गांव की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 800 रुपए से बढ़कर 28,000 हो गई है। यानी पांच व्यक्तियों के परिवार की औसत आय 1.25 लाख रुपए साल है।

पूरे देश में आंगनबाड़ियों का जो हाल है, वह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन लगभग आधे एकड़ में फैली यहां की आंगनबाड़ी की दीवारें बोलती हैं। इस आंगनबाड़ी के आंगन में फिसल पट्टी है, पर्याप्त खेल–खिलौने हैं, हरेक बच्चे के लिए अच्छा, सादा, स्वादिष्ट भोजन, अलग–अलग बर्तन, साफ पानी की व्यवस्था है। बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होता है। यहां बच्चे कुपोषित नहीं हैं। यह आंगनबाड़ी समय सीमा से भी नहीं बंधी है। गांव वाले जानते हैं कि बच्चे का मानसिक व शारीरिक विकास छह वर्ष की उम्र में ही होता है तो फिर आंगनबाड़ी तो बेहतर होनी ही चाहिए। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता ईराबाई मारुति कहती हैं कि जब इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है तो फिर मैं क्यो कतराऊं! मैं कुछ गड़बड़ करती हूं तो मुझे ग्राम सभा में जवाब देना होता है। वे बड़े गर्व से कहती हैं कि मेरी आंगनबाड़ी को केंद्र सरकार से सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी का पुरस्कार मिला है। पोपटराव बताते हैं कि हमारे गांव में पहले से ही दो आंगनबाड़ियां थीं और फिर तीसरी आंगनबाड़ी बनाने का पत्र आया। हम सभी लोगों ने विचार किया कि हमारे यहां बच्चों की संख्या उतनी तो है नहीं कि तीसरी आंगनबाड़ी होनी चाहिए। हमने शासन को पत्र लिखकर तीसरी आंगनबाड़ी के प्रस्ताव को लौटा दिया।

गांव की पाठशाला में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पहले बच्चों को पांचवीं के बाद से ही गांव के बाहर जाना पड़ता था। अधिकांश बालिकाएं पढ़ना छोड़ देती थीं। अब स्कूल हायर सेकेंड्री तक हो गया है। स्कूल का समय शासन के अनुसार नहीं चलता है। उसे ग्राम सभा तय करती है। स्कूल में दोपहर का भोजन भिक्षा के रूप में नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकार के रूप में दिया जाता है। शिक्षिका शोभा थांगे कहती हैं कि हम लोग तो गरमियों की छुट्टी में भी स्कूल आते हैं। आज इस गांव में पढ़ाई शहर के किसी बड़े स्कूल से भी बेहतर होती है। यही कारण है कि आज हिवरे बाजार के इस गांव में आसपास के गांवों और शहरों तक से बच्चे पढ़ने आने लगे हैं। पोपटराव कहते हैं कि हमारे यहां शिक्षकों के लिए ग्राम सभा में तो आना जरूरी है, लेकिन चुनाव ड्यूटी में जाने की आवश्यकता नहीं है।

गांव में स्थानीय स्तर पर मिलने वाली समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम आसानी से मिल जाएंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य सेविका लता एकनाथ कहती हैं कि गांव में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी है। यदि मुझसे गड़बड़ी होती है तो ग्राम सभा में जवाब देना होता है।

अब जरा बात करें देश में सबसे भ्रष्ट राशन व्यवस्था की। 'राशन व्यवस्था में यहां सबसे पहले तो प्रत्येक कार्डधारी को राशन बांटा जाता है, लेकिन उसके बाद राशन बचने पर ग्राम सभा तय करती है कि इस राशन का क्या होगा ? ग्राम सभा कहती है कि इसे अमुक परिवार को दे दीजिए, तो मुझे देना होता है। मैं मना नहीं कर सकता हूं।' राशन दुकान संचालक आबेदास थांगे समझाते हैं, 'मुझे फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत नहीं देनी होती है।

मेरी तौल में कुछ दिक्कत हो या कुछ और तो मुझसे ग्राम सभा में जवाब तलब किया जाता है। और जब मुझे रिश्वत नहीं देनी है तो फिर मैं फर्जीवाड़ा क्यों करूं ?'

पोपटराव कहते हैं कि 1995 में हमने भूमि बंदोबस्त की बात की तो कुछ लोगों ने विरोध किया। लेकिन सब कुछ था तो गांव के हित में ही। किसान नामदेव जयवंता थांगे कहते हैं कि मैंने पहले विरोध किया, लेकिन बाद में गांव हित में जमीन दी। आज चारों ओर हरियाली है। पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है। राव कहते हैं कि अब बाहरी लोगों की नजर हमारी जमीन पर है। हमने नियम बना दिया है कि हमारी जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी। इससे गरीब हमेशा गरीब रहेगा तथा अमीर और अमीर हो जाएगा। नजर तो सेज वगैरह के लिए भी लगी थी।

ये सारे महत्त्वपूर्ण निर्णय जहां पर बैठकर लिए जाते हैं, उस जगह का नाम है ग्राम संसद। इसकी बनावट भी दिल्ली के संसद भवन की ही तरह है। पोपटराव कहते हैं कि पहले तो गांव में दो ग्राम सभायें होती थीं, लेकिन हमने बाद में अपनी जरूरत के मुताबिक ग्राम सभायें करनी शुरू कीं। हम महीने में चार ग्राम सभायें करते हैं। वास्तव में हमारी यह ग्राम सभा निर्णय सभा है। हम ग्राम सभा में कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति आए और बात करे। महिलायें विशेष रूप से आयें और अपनी बात रखें। यह तभी होगा जब उनकी बात को सुना जाये। यदि नहीं सुना जाएगा तो फिर वे ग्राम सभा में आयेंगी ही क्यों ? फिर कहां रह जायेगी ये ग्राम सत्ता ?

यही नहीं, ग्राम सभा ने कुछ और फैसले लिए जिनके बगैर हिवरे बाजार की बात अधूरी होगी। यहां बस एक ही मुस्लिम परिवार है रहमान सैयद का। हिवरे बाजार की ग्राम सभा ने इस परिवार के लिए श्रमदान से मस्जिद बनाने का फैसला लिया। ग्राम सभा ने यह भी सोचा कि सरपंच तो इतनी जगह घूमते हैं और उनके लिए वाहन की बहुत जरूरत है, तो फिर क्या ! दस दिनों में पांच लाख रुपए की व्यवस्था हो गई। वाहन आया और अब यह वाहन गांव का वाहन है। पोपटराव जहां भी जाते हैं, वहां वे बच्चों, महिलाओं और किसानों को ले जाते हैं। इससे उनका एक्सपोज़र होता है और हमारे गांव की सामूहिक दृष्टि मजबूत होती है। यही कारण है कि 1989 के बाद से यहां चुनाव नहीं हुए। चुनाव की तारीख आती है और निर्विरोध सत्ता सौंप दी जाती है पोपटराव पवार के हाथों में।

पारदर्शिता यहां मुंह नहीं चिढ़ाती है। यहां पंचायत भवन में प्रतिमाह पैसों का पूरा रिकॉर्ड लिख कर टांग दिया जाता है। पंचायत सचिव ज्ञानेश्वर लक्ष्मण कहते हैं कि साल के अंत में ग्राम सभा का पूरा रिकॉर्ड गांव वालों के सामने और बाहरी लोगों को बुलाकर बताया जाता है।

हिवरे बाजार को इस साल देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार राष्ट्रपति ने दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी हिवरे बाजार को अनेक पुरस्कार दिए हैं। रोजाना बाहरी लोग गांव को देखने और स्वराज को समझने यहां आते हैं। एक समय था जब गांव में हर आठवें दिन पुलिस आ जाती थी। उस समय यह ऐसा गांव था कि नवयुवक आस–पास में यह बताने से कतराते थे कि हम हिवरे बाजार के निवासी हैं। आज लोग अपने नाम के साथ गांव का नाम जोड़कर बताते हैं।

इंडिया वाटर पोर्टल की सामग्री पर आधारित

शांत किंतु सफल शुरुआत

ललित माथुर

आंध्र प्रदेश सरकार ने शांत तथा विनम्र तरीके से एक विशिष्ट सफलता हासिल कर दो वर्षों से भी कम समय में एक शांतिपूर्ण क्रांति के बीज बो दिए। यह सफलता है : सूचना के अधिकार नियम का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक अंकेक्षण करवाना। सरकार अंकेक्षण ही नहीं करवाती, बल्कि उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है – वह भी व्यापक रूप से तथा विवरण पर नजर रखते हुए। सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का एक चरण समाप्त हो चुका है तथा दूसरा शुरू होने वाला है। इसका काफी अच्छा असर हो रहा है, क्योंकि सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली है : इसने अपनी पारदर्शिता की वजह से खासी लोकप्रियता भी हासिल कर ली है और यह किसी

भी तरीके से दिखावे का मामला नहीं लगता।

करीम नगर जिले में थिम्मापुर मंडल के कोल्लामपाली गांव में, मंडल(आंध्र प्रदेश में ब्लॉक की जगह मंडल ने ले ली है) मुख्यालय पर जन बैठक के एक दिन पहले सामाजिक अंकेक्षण अपने अंतिम चरणों में था। इसका मतलब है कि मंडल परिषद विकास अधिकारी से रिकॉर्ड लेकर जांच की गई थी। घर–घर जाकर सत्यापन किया जा चुका था; फील्ड तथा तकनीकी सहायकों और मेटों से विषमताओं पर चर्चा हो चुकी थी। कई मामलों में फील्ड सहायक तथा मेटों ने पैसों में गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए बयान पर हस्ताक्षर किए तथा उसकी पूर्ति का वायदा किया।

सत्यापन की प्रक्रिया

यह गांव में पहला सामाजिक अंकेक्षण था। इसमें वर्ष 2006–07, 2007–08 और 2008–09 की अवधि के दौरान हुए विकास कार्यों का सत्यापन किया जाना था। कोल्लामपाल्ली एक बड़ा गांव है और इसने विभिन्न कार्यों में, जैसे सिंचाई टैकों में डीसिल्टिंग, टंकियों के निर्माण, भूमि उत्खनन, पौधारोपण, भूमि विकास तथा अनुसूचित जातियों और गरीब किसानों के लिए सिंचाई के लिए कुएं खोदने में करीब एक करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सामाजिक अंकेक्षण के लिए छह ग्रामीणों को, जो आस–पड़ौस के गांवों के कृषि मजदूर परिवारों से थे, प्रशिक्षण दिया गया। सभी युवा थे। महाविद्यालय में पढ़ने वाले चार छात्राएं और दो छात्र। इनका चयन और प्रशिक्षण डीआरपी ने किया था।

एक वार्ड सभा की बैठक में करीब 100 लोग थे। इसमें बहुमत नरेगा के अंतर्गत काम कर रही महिलाओं का था। दर्शकों ने सक्रियता से भाग लिया। जब भी गलत नामों तथा राशियों वाला रिकार्ड आता तो दर्शक उत्तेजित हो उठते। मंडल बैठक में करीमनगर के जिला परिषद अध्यक्ष तथा अन्य जिलाधिकारी भी उपस्थित थे। करीब 20,000 रुपए फील्ड सहायकों तथा मेटों द्वारा लौटाया गया। जनता के बीच गबन की गई अन्य राशियों को लौटाने के वायदे किए गए तथा समय सीमा नियत की गई। जब सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं की चर्चा हो रही थी, जिला परिषद अध्यक्ष ने न केवल पैसे लौटाने की बात की, बल्कि यह भी कहा कि सरपंच के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मल्लापल्ली मंडल बैठक में 20 ग्राम पंचायतों से करीब 1,500 लोगों ने भाग लिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट बारी–बारी से पढ़ी गई। इनमें न केवल असंगतियां तथा अनियमितताएं थीं, बल्कि अच्छे कार्य भी थे। चर्चा मुक्त, दबावरहित, पारदर्शी तथा सजीव थी।

एक गांव में बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें सिर्फ आधी मजदूरी दी गई है। फील्ड सहायक इस बात से सहमत था, परंतु उसका कहना था कि केवल आधा काम किया गया था। चूंकि मजदूरी का आकलन किए गए काम के आधार पर होता है इसीलिए भुगतान सही था। दूसरी ओर, महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने पूरे दिन काम किया है इसीलिए उन्हें भुगतान भी पूरा होना चाहिए। अतः परियोजना अधिकारी ने मंडल परिषद विकास अधिकारी को तीन दिन के अंदर इंजीनियर के साथ गांव का दौरा कर मस्टर रोलों की जांच तथा नामों के सत्यापन का निर्देश दिया। इसका अगली बैठक में पुनरावलोकन किया जाएगा। गांव वाले इस आश्वासन से संतुष्ट थे।

कुछ गांवों में लोगों ने बताया कि उन्हें किए गए काम का भुगतान नहीं किया गया है। जब परियोजना निदेशक ने पासबुक में दर्ज भुगतान की तुलना जॉब कार्ड में दर्ज भुगतान से करनी चाही, तो जॉब कार्ड के अंदर के पन्ने, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का हिसाब दर्ज होता है, गायब पाए। जॉब कार्ड अधूरा भी था। यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि किसी भी मंडल में ऐसा नहीं हुआ था। मंडल परिषद विकास अधिकारी को पूर्ण जॉब कार्ड जारी करने, कमियों की जांच, जिम्मेदारियों को तय करने तथा रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए।

मल्लापल्ली मंडल के ग्राम सामाजिक अंकेक्षक – उनमें से आधी महिलाएं थी तथा सभी युवा थे – ज्यादातर अनुसूचित जातियों तथा मजदूर परिवारों से थे। स्पष्ट है कि यह उत्साहित समूह न सिर्फ सरकार, बल्कि समुदाय के लिए एक मूल्यवान स्रोत बन सकता है।

थिम्मापुर मंडल का चयन स्मार्ट कार्ड के जरिए भुगतान के लिए पायलट परियोजना के रूप में किया गया है। सबसे ज्यादा

प्रोत्साहित करने वाला पक्ष यह है कि यह सब वास्तव में होने लगा है।
यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि राजनीतिज्ञों ने इसमें समर्थन दिया है। खुद उन्हें इस प्रक्रिया में एक विश्वसनीय जन फोरम में उपस्थित होने का मौका मिला है। दूसरे चरण में कम भ्रष्टाचार, उच्च दर्जे का काम तथा प्रभावी निरीक्षण देखने को मिला। सामाजिक अंकेक्षण समूह को अन्य कार्यक्रमों में परामर्शदाता के रूप में बुलाया गया। यह सब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त जानकारियों के बिना संभव नहीं था, जो बगैर सरकारी निर्देशों के नहीं मिल सकती थीं। अब अन्य राज्यों को सामाजिक अंकेक्षण की यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

द हिंदु, 1 मार्च, 2009 से साभार

एक अक्षय ई–केंद्र के लिए कुछ आंसू

रीमा नरेंद्रन

तिरुवनंतपुरम के प्रथम अक्षय ई–केंद्र के ठेकेदार सोमसुन्दरम इन दिनों भारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पत्नी, बीमार ससुर, उनकी सास तथा तीन छोटे बच्चों, जिन्हें मुश्किल से एक वक्त का खाना मिल पाता है।
अक्षय ई–केंद्र साक्षरता में भाग लेने वाले शहर के प्रथम व्यक्ति सोमसुंदरम ने बताया, मैंने इस पंचायत के सैकड़ों बच्चों को बिना एक पाई लिए कम्प्यूटर सिखाया है। अब जब मेरे खुद के बच्चे बिना भोजन तथा स्कूल फीस नहीं दे सकने के कारण घर पर बैठे हैं, तो मुझे अपनी हार का एहसास होता है। सबसे दुखद यह है कि बैंक लोन नहीं चुका सकने के कारण उन्हें बेदखली का नोटिस मिल चुका है।
सोमसुंदरम राज्य के ई–साक्षरता कार्यक्रम से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कोवलम जंकशन में एक अक्षय केंद्र की स्थापना के लिए केनरा बैंक से दो लाख रुपए का लोन लिया। इसके अलावा, वेंगानूर पंचायत में अलग–अलग ठेकेदारों द्वारा तीन और अक्षय केंद्र खोले गए थे। कोवलम की वार्ड सदस्य, शोभना कुमारी ने बताया, सोमसुंदरम ने खुद के लिए आवंटित क्षेत्रों में कड़ी मेहनत की, जिससे अब वेल्लार, कोवलम, थोसीचिल तथा मुट्टाकोण में 90 प्रतिशत ई–साक्षरता है। वहीं बाकी के तीन केंद्र विफल रहे। जब पूरी पंचायत का मूल्यांकन किया जाता है तो इंफर्मेशन केरल मिशन इस कोशिश को विफल बताता है।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी जी–जान से मेहनत करने वाले सोमसुंदरम ने अनुसूचित जाति–जनजाति के छात्रों को ही नहीं, सामान्य वर्ग के छात्रों को भी बिना फीस लिए पढ़ाया है। जो अक्षय केंद्र नहीं जा सकते थे, उनके लिए पास के घरों में कम्प्यूटर रखवाया। पंचायत के सभी पांच वार्ड आज ई साक्षर हैं तथा इसका श्रेय इस प्रतिबद्ध व्यक्ति को है, वेंगानूर पंचायत अध्यक्ष शीला बरदन ने बताया।
पंचायत के उपकेंद्रों की स्थापना में सोमसुंदरम पर अच्छा खासा कर्ज चढ़ गया। कम्प्यूटर खरीदे जाने थे तथा अध्यापकों को वेतन दिया जाना था। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी के मकान को गिरवी रखते हुए एसबीटी तथा एक स्थानीय चिट फंड से और दो लोन लिए। सोमसुंदरम कहते हैं, 'मैं एक अनाथ हूं। मैंने अपनी शादी के समय किसी भी तरह का दहेज नहीं लिया। मैं कभी भी अपने सास–ससुर के लिए कोई समस्या नहीं खड़ी करना चाहता था। अब मुझे यह देखकर दुख होता है कि उन्हें अपने बुढ़ापे में मेरी वजह से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से बचने के लिए क्या करूं।'
परिवार की स्थिति इस समय दयनीय है तथा उनका चूल्हा यदा–कदा ही जलता है। मानसिक परेशानियों की तो बात ही नहीं की जा सकती। सोमसुंदर सरकार से मिलने वाले पैसों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पंचायत तक हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। उन्होंने बताया, 'मैं इस परियोजना को अपनी पंचायत में सफल बनाना चाहता था। मुझे यह सरकार की एक अच्छी पहल लगी। लेकिन अब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता, जो मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल सके।'
शोभना कुमारी ने बताया कि आई टी मिशन ने कार्यक्रम की निगरानी तथा प्रचालन के लिए

बहुत कम प्रयास किए। उनके अनुसार, यह कार्यक्रम काफी प्रभावशाली तरीके से चलाया जा सकता था। द्वितीय चरण में उन्होंने इन केंद्रों को टेलीफोन तथा बिजली के बिलों के ई–भुगतान के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया था। इन भुगतानों से मिलने वाला सेवा–शुल्क इन ठेकेदारों के लिए आमदनी का स्रोत होता। लेकिन सचाई तो यह है कि यह सब लागू नहीं हुआ और अब तो पंचायत की भी इसमें कोई रुचि नहीं रह गई है।

पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि वेंगानूर पंचायत जितना भी पैसा दिया जाना था, दे चुकी है। परंतु अक्षय के जिला कार्यालय का कहना है कि अक्षय के ठेकेदारों के भुगतान में हो रहे विलंब का कारण तिरुवनंतपुरम जिला पंचायत द्वारा अपने हिस्से का पैसा नहीं जमा करना है। उप जिला संयोजक रामचंद्रन का कहना है, 'ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक पंचायत अपना हिस्सा दे चुकी हैं। अब अगर जिला पंचायत अपने हिस्से का धन सौंप दे तो हम भुगतान कर सकते हैं।'

चूंकि गरीबी रेखा से नीचे जी रहा यह परिवार एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत का सामना कर रहा है। अतः यदि कोई इनकी मदद करना चाहे तो वह सोमसुंदरम से 9349874555 पर संपर्क कर सकता है। निवेदन है कि कॉलर टोन से आश्चर्यचकित न हों, जो हर बार यही करता है, जीविया थोनी थुझंझु थुझंझु...... यानी किसी तरह खेते हैं जीवन की नाव।

इंडियन एक्सप्रेस से साभार

ग्राम पंचायतों के लिए गूगल पुरस्कार

गूगल के लोकोपकारी हिस्से गूगल.आर्ग ने कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय प्रशासन में सर्वोत्तम रचनात्मकता को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। प्रतियोगिता के लिए आई प्रविष्टियों का मूल्यांकन सशक्तीकरण तथा नवाचार के आधार पर किया जाएगा। नवाचार निम्नलिखित छह क्षेत्रों में से कम से कम एक में होनी चाहिए – शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, जल आपूर्ति, ग्रामीण संरचना, ग्रामीण विद्युतीकरण, संसाधन एकत्र करना। पंचायतों को निम्नलिखित का प्रदर्शन करना होगा : गांव के निर्णय तथा योजना की प्रक्रिया में सभी सामाजिक और आय वर्गों के लोगों का समावेश, गांव वालों के साथ सूचनाओं का आदान–प्रदान आदि। 49 जिलों के 27,942 गांवों को सम्मिलित करने वाली इस प्रतियोगिता को गूगल.आर्ग ने 'सूचना तथा शक्ति' पहल के अंतर्गत शुरू किया है। सार्वजनिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति हर राज्य से पांच विजेताओं को चुनेगी। हर पुरस्कार 5,00,000 रुपए का होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उम्मीदवार www.google-org/ggpp.htpl पर जा सकते हैं अथवा कर्नाटक जिला पंचायत कार्यालय से आवेदन –पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष की प्रतियागिता 12 दिसंबर 2008 से 25 जनवरी 2009 के बीच आई प्रविष्टियों के लिए खुली थी। प्रविष्टियां तेलगु, कन्नड़, हिंदी या अंग्रेजी में भेजी जा सकती हैं।

पंचायती राज अपडेट से साभार

जलवायु परिवर्तन, महिलाएं और पंचायतें

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने प्लान इंटरनेशनल (इंडिया चैप्टर) और वाटर एड के सहयोग से 23–24 अप्रैल 2009 को सोलहवें महिला सशक्तीकरण दिवस समारोह का आयोजन किया। समारोह की विषयवस्तु थी : जलवायु परिवर्तन, महिलाएं और पंचायतें। समारोह का आयोजन राष्ट्रीय सहकारी संघ के सभागार में किया गया।

23 अप्रैल 2009 को प्रातः 10 बजे उद्घाटन सत्र की शुरुआत 'गर हो सके तो अब कोई शमा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए' गीत से हुई। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के निदेशक जॉर्ज मैथ्यू ने कहा कि 23 अप्रैल 1993 से, जब स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण संविधान का हिस्सा बना, महिला सशक्तीकरण को नए मायने मिले हैं। उन्होंने अपने भावपूर्ण भाषण में महिला पंचायत सदस्यों को भारतीय लोकतंत्र की रीढ़

बताया। मुख्य अतिथि मशहूर पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है, जो प्रदूषण, संसाधनों के क्षरण, भूख तथा गरीबी जैसी समस्याओं से भरी हुई है। विकास के विचार ने मनुष्य को प्रकृति का कसाई बना दिया है। मानवता का अंतिम लक्ष्य प्रकृति से संस्कृति की तरफ जाना है। यह सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाएं धरती मां को बचाने की जिम्मेदारी लें।'

वॉटर एड की नीति तथा सहयोगी निदेशक इंदिरा खुराना ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों का अभिवादन करते हुए उन्हें बधाई दी कि आज 2.4 लाख पंचायतें लगभग 2000 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं तथा इससे हमारे विकास तथा ग्रामीण विकास में वृद्धि हो रही है। प्लान इंटरनेशनल (इंडिया चैप्टर) की मुख्य राष्ट्रीय निदेशक भाग्यश्री डेंगले ने कहा, मैं जानती हूं आप में से बहुतों के लिए पुरुषों की उपस्थिति में बोल पाना भी काफी मुश्किल होता है। फिर भी आपने वे कार्य किए हैं जो शहरों में रहने वाली पढ़ी–लिखी महिलाएं भी नहीं कर पाई हैं। आपकी चेतना, चरित्र और शक्ति प्रशंसनीय है।

1998 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने विशिष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरस्कार की स्थापना की थी। तब से यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जा रहा है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, पट्टिका तथा चैक शामिल है। इस वर्ष के पुरस्कार–किरण कुमारी, सरपंच, कचहरी राज राघाई पंचायत, जिला मुजफ्फपुर, बिहार; रुगमिनि सुब्रमण्यन, अध्यक्ष, पूठादि ग्राम पंचायत, जिला वायनाड, केरल और मंजु शर्मा प्रधान, छुटमुलपुर ग्राम पंचायत, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को पंयायतों में उनके योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रदान किए गए।

पूर्ण तथा कार्य समूह सत्र

पूर्ण तथा कार्य समूह सत्रों में प्रतिनिधियों ने हरित ऊर्जा, जल तथा जलवायु परिवर्तन, पेय जल तथा पंचायतें, पंचायतों के जरिए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना, कमजोर तबकों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा ग्रीन हाउस प्रभाव से बढ़ती परेशानियां आदि विषयों पर विचार–विमर्श किया। सभी सत्रों में महिला प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मशहूर विशेषज्ञों जैसे –मैग्सेसे पुरस्कार विजेता तथा तरुण भारत संघ के महासचिव राजेंद्र सिंह, पर्यावरण विशेषज्ञ शांथा हरिहरन, वाटर एड में सिटिजन्स रिपोर्ट इनीशिएटिव के राष्ट्रीय समन्वयक रिचर्ड महापात्रा, पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर गोपाल अय्यर, यूएनडीपी में डीसेंट्रलाइजेशन कम्युनिटी सॉल्यूशन एक्सचेंज के मॉडरेटर जॉय एलामोन, इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो बी.एस. बाविसकर और संयुक्त निदेशक आश नारायण राय, वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी, पानी बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले पर्यावरणविद् अरुण कुमार और भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सह आयुक्त महिपाल की उपस्थिति तथा भागीदारी ने चर्चा का स्तर ऊंचा उठाने में मदद की।

समापन सत्र

समापन सत्र की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की निदेशक वर्षा दास थीं। उन्होंने सभी पंचायत सदस्यों का एकजुट होकर धरती को बचाने का प्रयास करने के लिए आहवान किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने बताया कि इन दो दिनों के सत्रों में भागीदारी का उनका अनुभव काफी अच्छा रहा। अर्चना कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म 'यह हमारे साथ क्यों हुआ' तथा ग्लेशियरों के सिकुड़ने, समुद्र के जल स्तर के बढ़ने, सुंदरबन तथा हिमाचल प्रदेश के सेबों पर आधारित फिल्मों को दर्शकों ने विशेष रुचि के साथ देखा।

सभी महिला प्रतिनिधियों ने अपनी पंचायतों में पेड़ लगाने की शपथ ली। उन्होंने अपनी पंचायतों के जरिए बेहतर जागरूकता, बेहतर पर्यावरण तथा सभी के लिए बेहतर दुनिया के लिए काम करने के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता जाहिर की। जब सभी प्रतिभागियों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया तो समूचा सभा स्थल एकता, अभिन्नता, शक्ति तथा दृढ़ निश्चय की भावना से गुंजायमान हो उठा।

पंचायती राज अपडेट से साभार

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट : www.isst-india.org फोन : 91-11-47682222, 24653780